

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3877
जिसका उत्तर 18 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।
27 अग्रहायण, 1946 (शक)

ग्रीनफील्ड ईएमसी

3877. श्री डगगुमल्ला प्रसाद राव:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रॉनिक्स संघटकों के आयात को विनियमित करने और इलेक्ट्रॉनिक्स संघटकों के निर्यात-मुखी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
- (ख) देश में 'इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर' (ईएमसी) योजना के अंतर्गत अनुमोदित 'ग्रीनफील्ड ईएमसी' और सामान्य सुविधा केन्द्रों की राज्यवार कुल कितनी है;
- (ग) ईएमसी 2.0 योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से अब तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है और इसके लिए कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;
- (घ) प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों के लिए कुल कितनी विदेशी कंपनियों को अनुमति दी गई है और इसमें कितनी प्रगति हुई है;
- (ङ) भारत को 'इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन' और विनिर्माण (ईएसडीएम) केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और इनमें अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क): इलेक्ट्रॉनिकी घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक और गहरा बनाने के लिए, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस) और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) नामक योजनाएं शुरू की हैं। एसपीईसीएस के अंतर्गत देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के घरेलू विनिर्माण की डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह, उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लक्षित खंड के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए पीएलआई 5 वर्ष की अवधि के लिए लक्षित सेजमेंट को वृद्धिशील बिक्री पर 6% से 4% का प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गयी है। नियामक ढांचे को मजबूत करने और भारत को इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों को **अनुबंध-I** में दर्शाया गया है।

(ख): इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु 22 अक्टूबर 2012 को इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना अधिसूचित की गयी थी। 21 अक्टूबर, 2017 से इस योजना के लिए आवेदन प्राप्त करना बंद कर दिया गया था। इस योजना के तहत, देश भर के पंद्रह (15) राज्यों में 1,470 करोड़ रुपये के केंद्रीय अनुदान सहित 3,499 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ 3,464 एकड़ क्षेत्र में 19 ग्रीनफील्ड ईएमसी और 3 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने के बारे में मंजूरी दी गई थी। राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): 01.04.2020 को अधिसूचित संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना के तहत, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के कोप्पर्थी में 540 एकड़ क्षेत्र में ईएमसी परियोजना की स्थापना के लिए मैसर्स आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम (एपीआईआईसी) से एक आवेदन प्राप्त हुआ है। इसे 18.03.2021 को 748.76 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ मंजूरी दी गई है, जिसमें 350.00 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल है।

(घ): अप्रैल 2019 के बाद से भारत को इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र की 356 कंपनियों से 3,290 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एफडीआई प्राप्त हुई है। 2019-20 के बाद से प्राप्त एफडीआई की वित्तीय प्रगति इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	निवेश (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
2019-20	422.37
2020-21	375.31
2021-22	416.99
2022-23	539.96
2023-24	695.75
2024-25 (Q2 अब तक)	839.57
कुल	3289.94
<i>स्रोत: एफडीआई सेल, डीपीआईआईटी</i>	

(ड): भारत को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों और योजनाओं को **अनुबंध-III** में दर्शाया गया है। इन नीतियों के परिणामस्वरूप, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन 2014-15 में 1.90 लाख करोड़ रुपये (30 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से बढ़कर 2023-24 में 17% से अधिक की सीएजीआर पर 9.52 लाख करोड़ रुपये (115 बिलियन अमेरिकी डॉलर) होगया है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात 2014-15 में 38,263 करोड़ रुपये (5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से बढ़कर 2023-24 में 2.41 लाख करोड़ रुपये (29.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) होगया है, जो 20% से अधिक की सीएजीआर दर पर बढ़ रहा है।

देशमें इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए नियामक वातावरण में सुधार के लिए निम्नलिखित सुधार किए गए हैं:

- 1. प्रमाणन में अधिक लचीलेपन के लिए अनिवार्य पंजीकरण आदेश:**
यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सुरक्षित मानकों के अनुरूप हैं, सरकार ने बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत बीआईएस अनुरूपता मूल्यांकन विनियमन, 2018 की योजना-II के अनुसार इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021 की अनुसूची के तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अधिसूचित किया है। ब्यौरा एमईआईटीवाई की वेबसाइट (<http://एमईआईटीवाई.gov.in/esdm/standards>) पर उपलब्ध है।
- 2. चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी):** सेलुलर मोबाइल हैंडसेट, कलाई में पहनने योग्य उपकरण (जिन्हें आमतौर पर स्मार्ट घड़ियों के रूप में जाना जाता है) और सुनने योग्य उपकरण तथा उनके उप-संयोजनों/इनपुटों/भागों/उप-भागों में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए पीएमपी को अधिसूचित किया गया है।
- 3. सार्वजनिक खरीद आदेश (पीपीओ):** सार्वजनिक खरीद आदेश के अंतर्गत की जाने वाली खरीद में घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि स्थानीय मूल्य संवर्धन में उत्तरोत्तर वृद्धि करके घरेलू उद्योग की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके, जिससे आत्मनिर्भरता के व्यापक लक्ष्य को पूरा किया जा सके।
- 4. सीएचआईएमपोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण को बंद करने के लिए आयात नीति में संशोधन:** डीजीएफटी ने अधिसूचना 41/2024-25 दिनांक 29.11.2024 के माध्यम से आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 85 के अंतर्गत आने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स के आयात के लिए आईटीसी एचएस कोड 85423100, 85423900, 85423200, 85429000 और 85423300 के लिए चिप आयात निगरानी प्रणाली (सीएचआईएम) के तहत अनिवार्य पंजीकरण को बंद कर दिया है। इससे इलेक्ट्रॉनिकी और सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी।
- 5. 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) :** मौजूदा एफडीआई नीतिके अनुसार, इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण (भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों को छोड़कर) के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई अनुमति है, जो लागू कानूनों/नियमों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन है। भूमि सीमा साझा करने वाले देशों को एफडीआई की मंजूरी प्रेस नोट 3 (पीएन 3) अधिसूचना के माध्यम से दी जा रही है।
- 6. पीएलआई क्षेत्र के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना:** सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए पीएलआई अनुमोदित कंपनियों से पीएलआई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी भी कंपनी के लिए पीएलआई व्यवसाय वीजा जारी करने की प्रक्रिया को संशोधित और विस्तारित किया है। इसके अलावा, पीएलआई व्यवसाय वीजा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है।
- 7. इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखला और एमओडब्ल्यू आरइकाइयों में रियायती दर (आईजीसीआर) पर माल के आयात पर स्पष्टीकरण:** CBIC ने परिपत्र संख्या 26/2024-सीमा शुल्क दिनांक 21.11.2024 के माध्यम से स्पष्ट किया कि मध्यवर्ती माल निर्माता द्वारा आयात किए गए सामान जो कि सेलुलर मोबाइल फोन के अंतिम निर्माता को कुछ विनिर्माण/मूल्य संवर्धन के बाद आगे की आपूर्ति के लिए एमओडब्ल्यू आरइकाइ है, आईजीसीआर नियम, 2022 के तहत शुल्क की रियायती दर के लाभ के लिए विधिवत पात्र हैं, जब तक कि अन्य सभी शर्तें पूरी होती हैं। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया है कि एमओडब्ल्यू आरइकाइ अब आईजीसीआर छूट के साथ-

साथशुल्कस्थगनकालाभउठासकतीहै,
बशर्तकिवहआईजीसीआरनियमोंऔरएमओडब्ल्यूआरप्रावधानोंमेंनिर्धारितशर्तोंकाअनुपालनकर
तीहो।

8. धारा 65 इकाईसेदूसरेगोदाम/धारा 65 इकाईमेंमालकीआवाजाहीपरस्पष्टीकरण:
सीबीआईसीनेनिर्देशसंख्या 16/2024- सीमाशुल्कदिनांक 25.06.2024
केतहतस्पष्टकियाहैकिधारा 65 इकाईसेदूसरेगोदाम/धारा 65
इकाईमेंपरिणामीमालकेहस्तांतरणकीअनुमतिएमओडब्ल्यूआरकेतहतनिर्धारितशर्तोंकेअनुपालन
केअधीनहै।

9. श्रव्यऔरधारणयोग्यवस्तुओंकेविनिर्माणकासमर्थनकरनेकेलिएसंशोधन:
सीबीआईसीनेअधिसूचनासंख्या 33/2023-सीमा शुल्कदिनांक 27.04.2023
केतहतश्रव्यऔरपहननेयोग्यवस्तुओंकीपीएमपीअधिसूचनामेंसंशोधनकिया,
जिसमेंकहागयाकिसीमाशुल्कअधिनियम, 1975
कीपहलीअनुसूचीकीव्याख्याकेसामान्यनियमोंकेनियम 2 (क)
काप्रावधानघटकों/इनपुट/भागों/उप-भागोंकेआयातपरलागूनीहोगा,
चाहेऐसेसामानएकसाथप्रस्तुतकिएगये हों।

10. टैरिफसंरचनाको युक्तिसंगत बनाना:
इलेक्ट्रॉनिकवस्तुओंकेघरेलूविनिर्माणकोबढ़ावादेनेकेलिएटैरिफसंरचनाकोयुक्तिसंगतबनायागया
है, जिसमेंअन्यबातोंकेसाथ-साथसेलुलरमोबाइलफोन, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिकघटक,
टीवीकेलिएसेटटॉपबॉक्स, एलईडीउत्पादऔरमेडिकलइलेक्ट्रॉनिकीउपकरणशामिलहैं।

11. पूंजीगतवस्तुओंपरमूलसीमाशुल्कसेछूट:
निर्दिष्टइलेक्ट्रॉनिकवस्तुओंकेविनिर्माणकेलिएअधिसूचितपूंजीगतवस्तुओंको "शून्य"
मूलसीमाशुल्कपरआयातकीअनुमतिहै।

12. प्रयुक्तसंयंत्रऔरमशीनरीकासरलीकृतआयात:
इलेक्ट्रॉनिकविनिर्माणउद्योगद्वाराउपयोगकेलिएएकमसेकम 5
वर्षोंकेअवशेषजीवनवालेप्रयुक्तसंयंत्रऔरमशीनरीकेआयातकोपर्यावरण,
वनऔरजलवायुपरिवर्तनमंत्रालयकीअधिसूचनादिनांक 11.06.2018
केअनुसार।खतरनाकऔरअन्यअपशिष्ट (प्रबंधनऔरसीमापारआवागमन) नियम, 2016
मेंसंशोधनकेमाध्यमसेसरलबनायागयाहै।

अनुबंध- II

क्र.सं.	राज्य	स्थान	क्षेत्रफल (एकड़में)	क्रियान्वयनएजें सी	वित्तीयपरिव्यय (करोड़रुपएमें)	
					परियोजना लागत	सहायता अनुदार
1	आंध्रप्रदेश	श्रीसिटी, सत्यवेदुमं डल, चित्तौड़जि ला	94	श्रीसिटीईएमसीप्राइवेट लिमिटेड	56.75	27.34
2		ईएमसी- 1@तिरुप ति, रेनिगुंटाऔ रयेरपाडुमं डल,	113.27	आंध्रप्रदेशऔद्योगिकअ वसंरचनानिगमलिमिटे ड (एपीआईआईसी)	74.27	37.14

क्र.सं.	राज्य	स्थान	क्षेत्रफल (एकड़में)	क्रियान्वयनएजें सी	वित्तीयपरिव्यय (करोड़रुपएमें)	
					परियोजना लागत	सहायता अनुदार
		चित्तौड़जि ला				
3		ईएमसी-॥ @तिरुपति , विक्रुतमा लागांव, येरपाडुमंड ल, चित्तौड़जि ला	501.40		248.9 0	98.46
4	असम	बोंगोरा, कामरूप जिला, असम	100	असमइलेक्ट्रॉनिकीवि कासनिगमलिमिटेड (AMTRON)	119.8 5	50.00
5	छत्तीसगढ़	सेक्टर-22, नयारायपुर	116.48	छत्तीसगढ़राज्यऔद्यो गिकविकासनिगमलि मिटेड (सीएसआईडीसी)	103.8 8	43.08
6	गोवा	तुएम, उत्तरगोवा जिला	147.55	विभाग ,गोवासरकार	161.3 2	73.77
7	गुजरात	मुंद्रा, कच्छजिला	631.38	मुंद्रासोलरटेक्नोपार्कप्रा इवेटलिमिटेड (एमएसटीपीएल)	745.1 4	315.69
8	झारखंड	आदित्यपुर , सरायकेला - खरसावां जिला	82.49	झारखंडऔद्योगिकक्षेत्र विकासप्राधिकरण (JIADA)	97.88	41.48
9	केरल	कक्कनाड, एर्नाकुलम जिला	66.87	केरलऔद्योगिकअवसं रचनाविकासनिगम (KINFRA)	35.06	15.89
10	मध्यप्रदेश	बड़वई- भोपाल	50	मध्यप्रदेशराज्यइलेक्ट्रॉ निकीविकासनिगमलि मिटेड(एमपीएसईडीसी)	47.19	20.86
11		पूर्वा- जबलपुर	40		38.57	17.76
12	ओडिशा	इन्फोवैली, भुवनेश्वर औद्योगिक क्षेत्र, खुर्दाजिला	203.37	ओडिशाऔद्योगिकवि कासनिगम (आईडीसीओ)	200.7 6	93.09
13	राजस्थान	सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र,	50.3	एल्सीनाइलेक्ट्रॉनिकीमै न्युफैक्चरिंगक्लस्टरप्रा इवेटलिमिटेड	46.09	20.24

क्र.सं.	राज्य	स्थान	क्षेत्रफल (एकड़में)	क्रियान्वयनएजें सी	वित्तीयपरिव्यय (करोड़रुपएमें)	
					परियोजना लागत	सहायता अनुदार
		खुशकेरा, भिवाड़ी		(ईईएमसीपीएल)		
14		करोलीऔ द्योगिकक्षेत्र , भिवाड़ी , जिला- अलवर	121.51	राजस्थानराज्यऔद्यो गिकविकासएवंनिवेश निगमलिमिटेड (आरआईआईसीओ)	29.13	11.49
15	तेलंगाना	ई-सिटी, हैदराबाद	603.52	तेलंगानाराज्यऔद्योगि कअवसंरचनानिगम (TSIIC)	667.6	252.42
16		महेश्वरम, रंगारेड्डी	310.70		436.9 7	138.6
17	उत्तरप्रदेश	इकोटेक- VI औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटरनोएडा	99.41	टेगनाइलेक्ट्रॉनिकीप्रा इवेटलिमिटेड (टीईपीएल)	115.3 2	50.00
18	पश्चिमबंगाल	फाल्टा, दक्षिण 24 परगनाजि ला	58.04	पश्चिमबंगालइलेक्ट्रॉनि कीउद्योगविकासनिगम लिमिटेड (WEBEL)	58.86	25.64
19		नैहाटी, उत्तर 24 परगनाजि ला	70		58.31	25.7
20	कर्नाटक (सीएफसी)	हेब्बलऔ द्योगिकक्षेत्र , मैसूर	1.50	मैसूरईएसडीएमक्लस्टर	48.53	32.31
21	महाराष्ट्र (सीएफसी)	शेन्द्राऔद्यो गिकक्षेत्र, औरंगाबाद जिला	1.98	देवगिरीइलेक्ट्रॉनिकी क्लस्टरप्राइवेटलिमिटे ड (डीईसीपीएल)	41.09	29.29
22		पिंपरीऔ द्योगिकक्षेत्र , पुणे	0.61	एमसीसीआईएइलेक्ट्रॉ निकक्लस्टरफाउंडेशन (एमईसीएफ)	67.00	50.00
कुल			3,464.38		3,499.63	1,470.25

अनुबंध- III

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 : राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 (एनपीई 2019) को 25.02.2019 को अधिसूचित किया गया है। एनपीई 2019 का उद्देश्य चिप सेट सहित मुख्य घटकों के विकास के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित और संचालित करके भारत को इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, और उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखला में बढ़े निवेश को आकर्षित करने और प्रोत्साहित करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्न लिखित योजनाएं और हस्तक्षेप किए गए हैं:

- सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए कार्यक्रम:**

इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को व्यापक और गहरा बनाने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15.12.2021 को सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये (> 10 बिलियन अमरीकी डॉलर) के परिव्यय के साथ एक व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी। कैबिनेट की मंजूरी के साथ, इस कार्यक्रम को हाल ही में 21.09.2022 को संशोधित किया गया है। संशोधित कार्यक्रम प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ-साथ मिश्रित सेमीकंडक्टर, पैकेजिंग और अन्य सेमीकंडक्टर सुविधाओं के लिए सेमीकंडक्टर फ़ैब्स के लिए समान रूप से परियोजना लागत का 50% राजकोषीय समर्थन प्रदान करता है।

पात्र आवेदकों के लिए अब निम्न लिखित वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध हैं:

 - सेमीकंडक्टर फ़ैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना:** यह देश में सेमीकंडक्टर वेफ़र निर्माण सुविधाएँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सभी प्रौद्योगिकी नोड्स में सिलिकॉन-आधारित सेमीकंडक्टर फ़ैब की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 50% वित्तीय सहायता उपलब्ध है।
 - डिस्प्ले फ़ैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना:** यह टीएफटी एलसीडी/एएमओएलईडी आधारित डिस्प्ले फ़ैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह परियोजना लागत का 50% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
 - भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर / सिलिकॉन फोटोनिक्स / सेंसर फ़ैब / डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फ़ैब्स और सेमीकंडक्टर एटीएमपी / ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना:** यह भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर / सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच) / सेंसर (एमईएमएस सहित) फ़ैब / डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फ़ैब्स और सेमीकंडक्टर एटीएमपी / ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को पूंजीगत व्यय का 50% राजकोषीय समर्थन प्रदान करती है।
 - डिजाइन लिंक प्रोत्साहन योजना:** यह आईसी, चिप सेट, एसओसी, सिस्टम और आईपीकोर और सेमीकंडक्टर लिंक डिजाइन के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन के विकास और परिणियोजन के विभिन्न चरणों में वित्तीय प्रोत्साहन, डिजाइन बुनियादी ढांचे का समर्थन प्रदान करती है। यह योजना "उत्पाद डिजाइन लिंक प्रोत्साहन" और "परिणियोजन लिंक प्रोत्साहन" दोनों प्रदान करती है।
- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को 01 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित किया गया था,** ताकि मोबाइल फोन विनिर्माण और असंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयों सहित निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण में शामिल पात्र कंपनियों को वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष की तुलना में) पर 4% से 6% का प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।
- आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई):** 03 मार्च, 2021 को अधिसूचित की गई थी, जिसका उद्देश्य पात्र कंपनियों को चार (4) वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्षित खंड के अंतर्गत आने वाले सामानों की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष की तुलना में) पर 4% से 2% / 1% का प्रोत्साहन प्रदान करना है।

पीएलआईयोजनाकेतहतलक्षितखंडमें (i) लैपटॉप (ii) टैबलेट (iii) ऑल-इन-वनपीसीऔर (iv) सर्वरशामिलहैं।

आईटीहार्डवेयरकेलिएउत्पादनसेजुड़ीप्रोत्साहनयोजना (पीएलआई) 2.0:
आईटीहार्डवेयरकेलिएपीएलआईयोजना 2.0 को29 मई, 2023 को 17,000 करोड़केबजटीयपरिव्ययकेसाथअधिसूचितकियागयाहै, जो6 वर्षोंकीअवधिकेलिएलक्षितखंडउत्पादोंकीशुद्धवृद्धिशीलबिक्री (आधारवर्षकीतुलनामें) परलगभग 5% काऔसतप्रोत्साहनप्रदानकरताहै। लक्षितखंडउत्पादोंमेंशामिलहैं: लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वनपीसी, सर्वरऔरअल्ट्रास्मॉलफॉर्मफैक्टर।

4. **इलेक्ट्रॉनिकघटकोंऔरसेमीकंडक्टरकेविनिर्माणकोबढ़ावादेनेकीयोजना (एसपीईसीएस) को 01 अप्रैल, 2020:**कोअधिसूचितकियागयाथा, ताकिइलेक्ट्रॉनिकउत्पादोंकीडाउनस्टीममूल्यश्रृंखला, यानीइलेक्ट्रॉनिकघटक, सेमीकंडक्टर/डिस्प्लेनिर्माणइकाइयाँ, एटीएमपीइकाइयाँ, विशेषउप-असेंबलीऔरउपरोक्तवस्तुओंकेविनिर्माणकेलिएपूँजीगतसामानशामिलकरनेवालीइलेक्ट्रॉनिकवस्तुओंकीपहचानकीगईसूचीकेलिएपूँजीगतव्ययपर 25% कावित्तीयप्रोत्साहनप्रदानकियाजासके। यहयोजना 31.03.2024 तकआवेदनप्राप्तकरनेकेलिएखुलीहै।
5. **संशोधितइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणक्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना:**प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को सप्लाई चेन सहित देश में अपनी इकाइयाँ स्थापित करने हेतुआकर्षितकरनेकेलिए रेडीबिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ) शेड / प्लगएंडप्लेजैसी सामान्य सुविधाओंके साथ विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु संशोधितइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणक्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना 01 अप्रैल, 2020 कोअधिसूचितकीगईथी। इसयोजना के अंतर्गतदेशभरमेंईएमसीपरियोजनाओंऔरसामान्यसुविधाकेंद्रों (सीएफसी) दोनोंकीस्थापनाकेलिएवित्तीयसहायतादी जातीहै। यहयोजनामार्च, 2024 तककीअवधिकेलिएआवेदनप्राप्ति हेतु खुली हैऔर मार्च, 2028 तक की आगे की अवधि में अनुमोदित परियोजनाओं के लिए निधियों का संवितरण किया जा सकता है।
6. **संशोधितविशेषप्रोत्साहनपैकेजयोजना (एम-एसआईपीएस)**
:इलेक्ट्रॉनिकविनिर्माणक्षेत्रमेंनिवेशआकर्षितकरनेऔरअक्षमताकीभरपाईकेलिएवित्तीयप्रोत्साहनप्रदान करनेहेतु 27 जुलाई, 2012 कोइसयोजनाकोअधिसूचितकियागयाथा। योजनाकीअवधिबढ़ाने, 15 औरउत्पादवर्तिकलकोशामिलकरकेयोजनाकादायराबढ़ानेऔरअधिकनिवेशआकर्षितकरनेकेलिएअगस्त, 2015 मेंइसमेंसंशोधनकियागयाथा। निवेशमेंतेजीलानेकेलिएजनवरी, 2017 मेंइसयोजनामेंऔरसंशोधनकियागयाथा। यहयोजनापूँजीगतव्ययकेलिएसब्सिडीप्रदानकरतीहै - विशेषआर्थिकक्षेत्रों (एसईजेड) मेंनिवेशकेलिए 20% औरगैर-एसईजेडमें 25%। प्रोत्साहनइलेक्ट्रॉनिकउत्पादोंऔरघटकोंकी 44 श्रेणियों / वर्तिकलकेलिएउपलब्धहैं, जोसंपूर्णइलेक्ट्रॉनिकविनिर्माणमूल्यश्रृंखलाकोकवरकरतेहैं। यहयोजना 31.12.2018 तकआवेदनप्राप्तकरनेकेलिएखुलीथीऔरकार्यान्वयनमोडमेंहै।
7. **इलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणक्लस्टर (ईएमसी) योजना:**
निवेशआकर्षितकरनेकेलिएसामान्यसुविधाओंऔरसुख-सुविधाओंकेसाथ-साथविश्वस्तरीयबुनियादीढांचेकेनिर्माणकेलिएसहायताप्रदानकरनेहेतुइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणक्लस्टरयोजना 22 अक्टूबर, 2012 कोअधिसूचितकीगईथी। आवेदनप्राप्तकरनेकीअंतिमतिथि 21 अक्टूबर, 2017 थीऔरधनराशिकावितरणमार्च, 2026 तकलागूहै।
8. **इलेक्ट्रॉनिकीविकासनिधि (ईडीएफ) :** इलेक्ट्रॉनिकीविकासनिधि (ईडीएफ) कोपेशेवररूपसेप्रबंधित "डॉटरफंड्स" मेंभागलेनेकेलिए "फंडऑफफंड्स" केरूपमेंस्थापितकियागयाहै, जोबदलेमेंइलेक्ट्रॉनिकीऔरसूचनाप्रौद्योगिकी (आईटी) केक्षेत्रमेंनईतकनीकविकसितकरनेवालीस्टार्टअप्सऔरकंपनियोंकोजोखिमपूँजीप्रदानकरेगा। इसफंडसेइनप्रौद्योगिकीक्षेत्रमेंअनुसंधानएवंविकासऔरनवाचारकोबढ़ावामिलनेकीउम्मीदहै।
